



अधिकारों का सम्मान

फैसले का वह हिस्सा खास तौर पर ध्यान देने लायक है, जिसमें जस्टिस आनंद वेंकटेश कहते हैं कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि मैं भी उन सामान्य लोगों के बहुमत का हिस्सा हूँ, जो होमोसेक्सुअलिटी को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।

राधा जोशी।।

मद्रास हाईकोर्ट ने LGBTQIA+ समुदायों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के पक्ष में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत के सामने मामला एक लेस्बियन कपल की इस शिकायत के रूप में आया था कि परिवार वालों द्वारा लापता बताए जाने के बाद उसे पुलिस प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। कोर्ट ने उस कपल को तो राहत दी ही, इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे तमाम मौकों को रेखांकित करने की कोशिश की, जहां LGBTQIA+ (यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, ए-सेक्सुअल प्लेस) समुदायों के सदस्यों को लांछन, उपेक्षा और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। यौन स्वायत्तता को निजता के

अधिकार का अहम हिस्सा बताते हुए कोर्ट ने ऐसे सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा, जिससे इन समुदायों के लोगों के साथ होने वाला गैरकानूनी भेदभाव खत्म हो। फैसले का वह हिस्सा खास तौर पर ध्यान देने लायक है, जिसमें जस्टिस आनंद वेंकटेश कहते हैं कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि मैं भी उन सामान्य लोगों के बहुमत का हिस्सा हूँ, जो होमोसेक्सुअलिटी को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अज्ञानता भेदभाव के किसी रूप को औचित्य प्रदान करने का आधार नहीं हो सकती। आश्चर्य नहीं कि यह फैसला न्यायिक, पुलिस और जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण के जरिए इन समुदायों के अधिकारों के

प्रति जागरूक बनाने की जरूरत बताता है। इसके अलावा स्कूलों में पैरेंट टीचर्स असोसिएशन जैसे मंचों के सहारे अभिभावकों में जागरूकता लाने और स्कूलों में जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम उपलब्ध कराने और फॉर्मों में मेल, फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर का विकल्प जोड़ने जैसे सुझाव भी काफी महत्वपूर्ण हैं। फैसले का एक अहम हिस्सा उन लोगों से संबंधित है, जो LGBTQIA+ समुदायों के लोगों के यौन व्यवहार को एक बीमारी बताते हैं और उसका तरह-तरह से इलाज करने का दावा करते हैं। इनमें अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े चिकित्सक भी नहीं धार्मिक संस्थानों से जुड़े गुरु भी शामिल हैं। कोर्ट ने ऐसे तमाम प्रयासों को निषिद्ध

घोषित कर दिया है। हालांकि अपने देश में सुप्रीम कोर्ट 2018 में ही कह चुका है कि दो वयस्कों के बीच स्वैच्छिक समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। इसके बावजूद समाज में प्रचलित पूर्वाग्रहों का प्रभाव इतना व्यापक है कि सरकार भी समलैंगिक शादी को मान्यता देने में हिचकती है क्योंकि उसके मुताबिक यह भारतीय परिवार की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि LGBT+ समुदायों को समाज में इसानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिलाने के लिए अभी कितना लंबा सफर तय करना है। बावजूद इसके, इसमें कोई शक नहीं कि मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला इस लंबी यात्रा में मील के एक अहम स्तंभ के रूप में दर्ज हुआ है।

धर्म प्रचार

अशोक वोहरा। सभी बातों का हिन्दू सनातन धर्म में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। गुमामी के काल में हजारों तरह के रीति रिवाजों का प्रचलन हुआ। प्रत्येक रिवाज के पीछे एक

धर्म-दर्शन



इतिहास छिपा हुआ है। धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिन्दू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिन्दू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा, तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या संन्यासी होने की जरूरत नहीं। स्वयं के धर्म की तारीफ करना और बुराइयों को नहीं सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा है।

संपादकीय

ट्रंप पॉलिसी बरकरार

क्वॉड में घोषणा हुई थी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैक्सीन उत्पादन और वितरण का एक केंद्र बनेगा, तो ब्लिंकन के आने के बाद यह साफ है कि अब भारत इसका हब बनेगा, जिसमें उसका साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देंगे। ब्लिंकन ने यह बात रखी कि कैसे उत्पादन बढ़े और भारत ने यह पक्ष रखा कि जो वैक्सीन प्रॉडक्शन हो, वह कैसे दुनिया के गरीब देशों तक भी पहुंचे, क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है, जब तक सारे सुरक्षित नहीं हैं। इस बात पर दोनों में ही सामंजस्य बना। ऐसे में यह साफ है कि अमेरिकी विदेश नीति में भारत का स्थान है काफी महत्वपूर्ण है। जबसे बाइडेन आए हैं, दोनों तरफ से उच्च स्तरीय संवाद बना हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ क्वॉड बनाने की जो घोषणा कुछ समय पहले की थी, उससे भारत में काफी विवाद खड़ा हुआ था। कई लोगों ने इस पर कहा था कि इसका क्या मतलब है, और यह बात अफगानिस्तान क्यों मानेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को केंद्र में रखकर कोई बात करे। लेकिन यहां आकर ब्लिंकन ने साफ किया कि ऐसा नहीं होने वाला और यह कि अमेरिका भारत को एक अहम भूमिका में देखता है। भारत के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। कहा जा रहा था कि ट्रंप प्रशासन के मुकाबले बाइडेन थोड़े टाइट होंगे, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के नेताओं का मिलना-जुलना जारी है, उससे साफ है कि बाइडेन ने भी ट्रंप की वह पॉलिसी जारी रखी है, जिसमें भारत के साथ काफी गर्माहट भरे रिश्ते बनाने की बात थी।

हमने देखा कि भारत में क्रिटिक्स को लग रहा था कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर बड़ा फोकस होगा। इससे भारत-अमेरिका के बीच एक बड़ा डायवर्जन खुलेगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इस ओर बड़ा झुकाव है।

बदली धारणा

हर्ष वी. पंत।।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के हालिया भारत दौरे से कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर आई हैं। अफगानिस्तान, चीन आदि के साथ ही ब्लिंकन ने तीन-चार चीजें टच की हैं। वैक्सीन डिप्लोमैसी को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रॉडक्शन के लिए 2.5 करोड़ डॉलर दिया है। क्वाड देशों में वैक्सीन प्रॉडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी बात की है। उनके आने से पहले हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की काफी चर्चा थी। हमने देखा कि भारत में क्रिटिक्स को लग रहा था कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर बड़ा फोकस होगा। इससे भारत-अमेरिका के बीच एक बड़ा डायवर्जन खुलेगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इस ओर बड़ा झुकाव है। मगर भारत और अमेरिका दोनों ने ही बड़ी मैच्योरिटी के साथ इस विषय को हैंडल किया। ब्लिंकन का बयान देखें तो उनका कहने का मतलब था कि उनके यहां भी चैलेंजर्स हैं और डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, इंडियन डेमोक्रेसी भी बढ़ रही है। और चूंकि हम डेमोक्रेसी हैं, इसलिए इस मामले में आपस में हम खुले तौर पर बात कर सकते हैं। भारत ने भी इस पर बात करने में कोई झिझक नहीं दिखाई और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय यह विषय ऐसा हुआ करते थे कि हम बहुत



नाजुक तरीके से उसे हैंडल करते थे। हम काफी नर्वस हो जाते थे कि मानवाधिकार या कश्मीर पर बात होगी तो हम क्या करेंगे। मगर अब भारत आत्मविश्वास से युक्त एक राष्ट्र की तरह इन विषयों पर दूसरे देशों से बात करने को तैयार दिखता है, खासकर अमेरिका के साथ। तो मुझे लगता है कि ब्लिंकन के दौरे के बाद रिश्तों में परिपक्वता एक अलग स्तर पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत चर्चाएं थीं और मोदी सरकार के आलोचक इसे बार-बार दोहरा रहे थे। अमेरिका में भी कई ऐसे आलोचक हैं, उनका अपना कॉक्स है। मानवाधिकार को लेकर प्रेशर गुप्स हैं जो बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ब्लिंकन ने इस विषय को

हिंदुस्तान में उठाया, वह दिखाता है कि दो परिपक्व लोकतंत्र किस तरह से नाजुक मसलों पर सहजता से संवाद कर सकते हैं और कैसे भारत और अमेरिका के बीच तनाव के आसार कम हो गए हैं।

यह तो सब मानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच संबंध अच्छे हो रहे हैं। चीन को भी दोनों देश एक तरह से ही देखते हैं। इसके चलते पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में काफी गर्माहट आई है। बाइडेन प्रशासन ने भी चीन को लेकर काफी कड़ा रुख अपनाया है। इसके चलते उनकी ओर से क्वॉड को ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा करने की कोशिश भी हो रही है। भारत का चीन के साथ जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, उससे भी स्पष्ट है कि भारत समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, जिसमें अमेरिका प्रमुख है। लेकिन जो समस्याएं बन रही थीं, वे चीन से संबंधित नहीं थीं। समस्याएं तो अफगानिस्तान और मानवाधिकार को लेकर बन रही थीं। ह्यूमन राइट्स में हमने देखा कि भारत और अमेरिका ने काफी कुछ मैनेज किया और अफगानिस्तान के मामले पर हमने देखा कि दोनों देश एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं। भारत और अमेरिका, दोनों ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक सुलह-समझौते के बगैर अफगानिस्तान में तालिबान एक लेजिटीमेट एक्टर की तरह काम नहीं कर सकता।

सूटोपु नवताल-5381		सूटोपु नवताल-5380 का हल			
4	6	3	8	9	7
1	9	6	5	4	
			8		
4	5			8	
2	5	4	6	1	
3			1	7	
	3				
5	9	7	2	6	
7	6	4	3	9	2

अपना ब्लॉग

अमेरिका अफगानिस्तान पर नजर बनाए रखेगा मोहन। राजनीतिक प्रक्रिया को दोनों ने प्राथमिकता में रखा है और यह बात अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर भारत में कही, क्योंकि भारत में इसे लेकर काफी अंदेशा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी नहीं कर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान पर नजर बनाए रखेगा, चाहे उसकी सेनाएं वहां से चली जाएं, चाहे वहां पर उसका फुटप्रिंट कम हो जाए, लेकिन आतंकवाद पर अंकुश लगाने का काम अमेरिका वह करता रहेगा। जो वैधता तालिबान को मिलनी है, वह राजनीतिक सुलह-समझौते के जरिए ही मिलेगी और इसमें सभी पक्षों को साथ रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इससे भारत में अफगानिस्तान को लेकर जो माहौल बन रहा था, वह बदला है। इससे भारत के अंदर भी थोड़ा भरोसा बढ़ा है इस बात को लेकर कि अमेरिका वहां भारत के हितों को भी ध्यान में रखेगा।

